साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार 29 मई- 4 जून 2023 वर्ष-9, अंक-7

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

कृषि मंत्री बोले | किसान, ग्रामीण और कृषि वैज्ञानिक खेती-किसानी पर सामूहिक चर्चा करेंगे

प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में नमो चौपाल का होगा निर्माण

भोपाल। जागत गांव हमार

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर नमो चौपाल का निर्माण किया जाएगा। मंत्री उज्जैन में हुए एग्री एक्सपो (कृषि मेले) के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नमो चौपाल पर किसान, ग्रामीण और कृषि वैज्ञानिक खेती-किसानी पर सामूहिक चर्चा करेंगे। मेले में उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों से आह्वान किया कि वे जैविक खेती की ओर आगे बढ़ें। मंत्री पटेल ने एग्री एक्सपो में लगाए गए विभिन्न स्टाल का अवलोकन किया। कृषि मंत्री ने कहा कि जननी जन्म-भूमि हम सबके लिए महान है। किसानों से आधुनिक खेती, उन्नत खेती, जैविक खेती आदि की चर्चा के लिए कृषि मेलों का आयोजन किया जा रहा है। किसानों के हित में मंडियों का सुदृीकरण किया गया है। उन्होंने कृषि संबंधित योजनाओं का विस्तार से जिक्र करते हुए किसानों से आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ लें। शिवराज सरकार किसानों की चिंता करने वाली सरकार है।

किसान जैविक खेती करें

उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसान अधिक से अधिक जैविक खेती करें। सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा कि मोटा अनाज का उपयोग अधिक से अधिक करें। मोटा अनाज खाने में अधिक उपयोग करें। स्थानीय विधायक पारस जैन ने कहा कि किसान जैविक खेती कर उत्पादन बढ़ाएं। मेले में बहादुर सिंह बोरमुंडला, अनिल जैन कालूहेड़ा, सोनू गेहलोत, भारत सिंह बैस, विनोद शर्मा, कमल आंजना, नाहर सिंह पंवार, किसान आदि उपस्थित थे।

आत्मा कार्यालय का लोकार्पण

मंत्री पटेल ने किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के परियोजना संचालक आत्मा के उज्जैन कार्यालय का लोकार्पण किया।

-डेढ़ लाख कर्मचारियों को हर माह तीन हजार रुपए का लाभ

भोपाल।

पंचायत सचिवों को शिवराज सरकार देगी 7वां वेतनमान!

चुनावी साल में सरकार ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े कर्मचारियों पंचायत सचिव, रोजगार सहायक और चौकीदारों का वेतन संबंधी मसले का निराकरण करने जा रही है। इसके तहत पंचायत सचिवों को शासकीय कर्मचारियों के समान सातवां वेतनमान का लाभ दिए जाने, रोजगार सहायकों और चौकीदारों का मानदेय बढ़ाने की योजना है। पंचायत एवं ग्रामीण और राजस्व विभागों ने करीब डेढ़ लाख 30 हजार से अधिक रोजगार सहायक, 52 हजार की संख्या वाले बड़े वर्ग चौकीदारों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहाने से मिलकर मांग की थी। मांग बढ़ाने संबंधी मामले में आने वाले वित्तीय भार का आकलन कर वित्त विभाग को प्रस्ताव दिया है। अब इसका परीक्षण किया जा रहा है। प्रदेश के 52 हजार गांवों में सीधे जनता से जुड़े इन कर्मचारियों के बारे में जल्द ही बड़ा फैसला लिया जाना है। राज्य सरकार का इन कर्मचारियों पर फोकस है।

जीआरएस को अभी 9000 मानदेय

दरअसल, इसी माह पंचायत सचिवों, रोजगार सहायकों और चौकीदारों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पंचायत एवं ग्रामीण विकास और राजस्व विभाग ने इस बारे में प्रस्ताव तैयार किया है। पंचायतों में 30 हजार से ज्यादा रोजगार सहायक हैं, जिन्हें केंद्र से मिलने वाले अनुदान के अनुसार 9000 रुपए मानदेय दिया जा रहा है। इसे बढ़ाकर डेढ़ गुना किया जाना है। इस हिसाब से इनका मानदेय 13500 रुपए किए जाने के प्रस्ताव है। प्रदेश में 52 हजार चौकीदारों में, जिनके पास सरकारी जमीन है उन्हें 400 रुपए और सरकारी जमीन न होने पर 4 हजार रुपए मानदेय दिया जा रहा है। इसे बढ़ाकर 6 हजार रुपए किया जाना प्रस्तावित है।

32 हजार सचिवों को अभी 6वां वेतनमान

प्रदेश में 32 हजार पंचायत सचिव हैं, जिन्हें अभी छठा वेतनमान दिया जा रहा है। उन्हें छठे वेतनमान में 5200-20200 वेतनमान में 2400 रुपए ग्रेड-पे मिल रही है। इस वेतनमान में छठे वेतनमान के अनुसार 150 प्रतिशत से ज्यादा महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है। इससे पंचायत सचिवों को 35 हजार रुपए मिल रहे हैं। पंचायत सचिवों को सातवां वेतनमान दिए जाने पर छठे वेतनमान में प्राप्त वेतन में फिटमेंट फॉर्मूले (2.56 प्रतिशत) के हिसाब से वेतन देय होगा, जिसमें प्रत्येक पंचायत सचिव को 2500 से 3000 रुपए का फायदा होगा और साल भर में अतिरि क्त वित्तीय भार 50 करोड़ रुपए अनुमानित है।

30 हजार रोजगार सहायक

चौकीदारों ने मुख्यमंत्री से मिलकर की थी मांग पंचायतों में 30 हजार से ज्यादा रोजगार सहायक हैं, जिन्हें केंद्र से मिलने वाले अनुदान के अनुसार 9000 रुपए मानदेय दिया जा रहा है। इसे बढ़ाकर डेढ़ गुना किया जाना है। इस हिसाब से इनका मानदेय 13500 रुपए किए जाने के प्रस्ताव हैं। प्रदेश में 52 हजार चौकीदारों में, जिनके पास सरकारी जमीन है उन्हें 400 रुपए और सरकारी जमीन न होने पर 4 हजार रुपए मानदेय दिया जा रहा है। इसे बढ़ाकर 6 हजार किया जाना प्रस्तावित है। जिन चौकीदारों के पास सरकारी जमीन है, उन्हें 400 रुपए मानदेय दिया जा रहा है।

50 करोड़ अतिरिक्त खर्च आएगा

2008 में पंचायत सचिवों का वेतन 1600 रुपए था। इसे 2018 में बढ़ाकर 35000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया था। इसे आगामी प्रस्ताव के अनुसार सातवें वेतनमान में बढ़ाया जाना है। इससे सरकार पर 50 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का अतिरिक्त खर्च आने की संभावना है।

मंडी शुल्क में छूट से दाल उद्योग नाखुश

भोपाल। कृषि विभाग ने तुवर पर मंडी शुल्क से राहत का आदेश जारी किया। इससे दाल उद्योग खुश होने के बजाय नाराज दिख रहे हैं। आल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन ने आदेश को अव्यावहारिक और पक्षपात पूर्ण करार दिया है। एसोसिएशन ने कहा कि इससे न तो प्रदेश के उद्योगों का भला हो रहा है, न किसानों का भला होने वाला है। सरकारी आदेश जारी होने के बाद आल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन ने दावा किया कि बीते चार वर्षों में प्रदेश में दाल मिलों ने अपना 50 प्रतिशत उत्पादन घटा दिया है। कुछ मिलें बंद होने के कगार पर हैं। वहीं, बहुत सी मिलों ने गुजरात या महाराष्ट्र पलायन कर लिया है। आल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने कहा कि सरकार ने ताजा छूट सिर्फ तुवर पर दी है। यह छूट भी सिर्फ मार्च तक के लिए दी गई है। वहीं मप्र में मुख्य रूप से सोयाबीन, गेहूं और चना की खेती होने के कारण उड़द, तुवर, मसूर जैसे अन्य दलहन बाहर से मंगवाने पड़ते हैं।

» सरकार की घोषणा को बताया अव्यावहारिक

» एक ही दलहन पर छूट देना उद्योगों के साथ अन्याय

एक जून को विश्व दुग्ध दिवस पर विशेष | एक वर्ष में 18 मेट्रिक टन दुग्ध का अधिक उत्पादन हुआ, सर्वाधिक उत्पादन मुरैना क्षेत्र में हो रहा

तेजी से बढ़ रहा ग्वालियर-चंबल अंचल में दुग्ध उत्पादन

ग्वालियर। दूध हमारे खानपान का विशिष्ट अंग है। माना भी जाता है, अगर फिट रहना है और बीमारियों से बचे रहना है तो सुबह-शाम एक-एक गिलास दूध जरूर पीना चाहिए। इस तथ्य को पूरे शहर ने कोविड के बाद जाना, तभी तो ग्वालियर चंबल अंचल में दूध की मांग बढ़ी। इसके बाद दुग्ध उत्पादन भी बढ़ गया। कोविड महामारी के दौरान वर्ष 2020-21 में जिंदगी की सांसें कमजोर होने लगी थीं, जिन्हें मजबूती देने के लिए अंचल में दुग्ध उत्पादन बढ़ाया गया। हालांकि कोविड की शुरुआत के साथ लाकडाउन लग गया था और कुछ ही घरों तक दूध पहुंचा। जिन्हें कोविड हुआ उन्हें चिकित्सकों ने इम्युनिटी मजबूत करने के लिए दूध का सेवन बताया। कोविड के बादल छंटने के बाद ही इसके घरों तक पहुंचने में निरंतरता आई। गत एक वर्ष में 18 मेट्रिक टन दुग्ध का अधिक उत्पादन हुआ। प्रादेशिक स्तर पर दुग्ध उत्पादन अहम स्थान बना लिया है। सर्वाधिक उत्पादन मुरैना क्षेत्र में हो रहा है। बहरहाल, हम एक जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाएंगे। इससे पूर्व जानें मप्र में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में हमारी स्थिति।

साल दर साल बढ़ा उत्पादन प्रति मेट्रिक टन में

जिला	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
ग्वालियर	468.00	500.47	462.46	488.11
दतिया	286.88	308.40	334.38	353.50
शिवपुरी	583.95	628.78	626.34	657.66
गुना	324.82	347.19	381.18	406.75
अशोकनगर	192.18	207.94	233.04	246.67
भिंड	445.96	466.87	513.00	515.52
मुरैना	741.11	791.53	866.09	914.49
श्योपुर	296.93	315.38	319.61	335.84

साल दर साल दुग्ध उत्पादन बढ़ रहा है। जिससे प्रदेश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादन की उपलब्धता बढ़ी है। ग्वालियर चंबल अंचल के किसान अब पशु पालन में रुचि दिखा रहे हैं। इसका नतीजा है कि दुग्ध उत्पादन बढ़ा। मुरैना में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन हो रहा है।
डॉ. अखिलेश पटेरिया,
अतिरिक्त उप संचालक, पशु विभाग ग्वालियर

दूध की अधिकता से गौ-पालक बन गया लखपति

मध्यप्रदेश में 'गौरी' की टक्कर में नहीं कोई गाय

-शाजापुर की देसी गाय दे रही 14.5 लीटर दूध

शाजापुर। जागत गांव हमार

गौरी जितना दूध देने वाली मालवी नस्ल की गाय पूरे मध्य प्रदेश में नहीं है। यह देसी गाय एक दिन में साढ़े 14 लीटर से ज्यादा दूध देती है। किसी देसी गाय का इतना दूध देना बहुत बड़ी बात है।

गौरी के इतनी मात्रा में एक दिन में दूध देने की खासियत ने उसके गौ-पालक को लखपति भी बना दिया है। दरअसल, गौरी ने अपने गौ-पालक को जिला स्तर पर 51 हजार का पुरस्कार दिलाया था तो वहीं अब राज्य स्तर पर दो लाख का ईनाम दिलाया है।

गौरी को राज्य स्तर पर मिले खिताब से गौ-पालक आशीष पुत्र महेश शर्मा मोहल्ला लालपुरा काफी खुश हैं। राज्य स्तरीय पुरस्कार कार्यक्रम का आयोजन रविवार को सुबह 10 बजे जिला बड़वानी में किया गया। अमूमन देसी मालवी नस्ल की गाय अक्सर मंडियों, चौराहों, हाईवे आदि जगह बेसहारा घूमती दिखाई दे जाती है।

पशु पालक इन्हें लावारिस सा छोड़ देते हैं, दाना पानी की आस में भटकती इन गायों को कोई दया कर घास, रोटी आदि खिला देते तो ठीक नहीं तो कई लोग तो इन्हें देखकर दरवाजा बंद कर देते हैं या कोई व्यवसायी लाठियां भांजकर इन बेसहारा गायों को धुत्कार देता है। लेकिन देसी मालवी नस्ल की गाय को अपना समझकर अच्छी देखरेख की जाए तो यह आपको ज्यादा से ज्यादा दूध तो देती ही है। वहीं गोबर से कंडे विक्रय कर भी अच्छी आमदनी दे सकती है।

गौरी को प्रतियोगिता में उतारा शाजापुर के लालपुरा निवासी गौ-पालक आशीष शर्मा एक अच्छे गौ-पालक हैं। इनके यहां देसी और गिर दो नस्ल की कुछ गाय हैं। इस साल मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के घटक के रूप में जिले का मूल गौवंशीय नस्ल मालवी एवं भारतीय उन्नत नस्ल की गाय के लिए पुरस्कार योजना अंतर्गत जिला स्तरीय पुरस्कार प्रतियोगिता का आयोजन शाजापुर में हुआ था। उन्होंने अपनी गाय गौरी को भी इस प्रतियोगिता में उतारा था। गौ-पालक शर्मा की मालवी नस्ल की गाय को प्रतिदिन औसत दुग्ध उत्पादन 14.760 लीटर दिया था। उन्हें जिला स्तर पर 51 हजार का पुरस्कार मिला था।

52 जिलों की आईं गाय

अब प्रदेश स्तर पर इस प्रतियोगिता में 52 जिलों की प्रथम आई गायों की मिल्किंग का मिलान किया गया तो देसी नस्ल की गायों में गौरी की मिल्किंग सबसे ज्यादा रही है। इसके बाद अब गौरी के प्रदेश स्तर पर सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय का खिताब मिलने पर गौ-पालक आशीष दो लाख रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

सातवीं पीढ़ी की गौरी

गौ-पालक आशीष बताते हैं कि वह गौरी सहित उनके पास जो अन्य गाय हैं उनकी सामान्य देखरेख ही करते हैं। चारा, भूसा, पशु आहार समय पर देते हैं। वहीं वह प्रतिदिन गायों के साथ कुछ वक्त जरूर बिताते हैं। उनकी गाय गौरी को वह दीपावली व अन्य त्योहारों पर शृंगार कर चांदी के कड़े पहनाते हैं। गोरी गाय उनकी यहां आई देसी गाय की सातवीं पीढ़ी है।

बगीचे के बीच खाली जगह में किसान उगा रहे फूल-सब्जी

आम के 165 पेड़ों से हर साल हो रही ढाई लाख की कमाई

पिता से ही खेती किसानी के गुर सीखे, अब हो गए आत्मनिर्भर

अशोकनगर। जागत गांव हमार

अशोकनगर जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर बलनाई गांव के किसान राजेंद्र सिंह यादव की पुश्तैनी जमीन इंदौर के पास थी। राजेंद्र ने 8वीं तक की पढ़ाई की, साथ में अपने पिता के साथ खेती करते रहे। पिता से ही खेती किसानी के गुर सीखे। इंदौर जिले के जिस इलाके में इनकी खेती थी, वहां सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था ठीक नहीं थी। भूजल स्तर भी काफी कम था। इसी वजह से मेहनत के बाद भी उम्मीद के मुताबिक पैदावार नहीं मिल पाती थी। इसी वजह से पुश्तैनी जमीन को बेच दिया और अशोकनगर के बलनाई गांव में आकर बस गए। यहीं पर जमीन भी खरीद ली और परंपरागत खेती करने लगे। 10 साल पहले खेती के अलावा कुछ करने की सोची। अपने खेत में आम के पौधे लगा दिए। शुरुआती देखरेख के बाद लागत की खास चिंता नहीं रहती है। अब हर साल ढाई लाख की कमाई हो रही है, साथ में परंपरागत खेती भी कर रहे हैं।

बेच दी अपनी पुस्तैनी जमीन- मैं इंदौर की सांवेर तहसील के धरमपुरी के किसान परिवार से हूं। मेरे पिता की 10 बीघा जमीन धरमपुरी में थी। वे बाकी किसानों की तरह सामान्य रूप से खेती किया करते थे। मैं पढ़ाई के साथ-साथ अपने पिता के साथ खेती में हाथ बंटाता। पिता ने ही मुझे खेती करने के तरीके समझाए। आठवीं क्लास के बाद मैं स्कूल नहीं गया और पूर्णकालिक किसान बन गया। धरमपुरी में रहने के दौरान ही अशोकनगर अपने रिश्तेदारों से मिलने-जुलने आता था। मैंने देखा कि यहां सांवेर की अपेक्षा जमीन में ज्यादा पानी है, जमीन भी उपजाऊ है। 1995 में मैंने सांवेर की 10 बीघा जमीन करीब 3 लाख 60 हजार में बेच दी।

यहां से शुरू हो गए अच्छे दिन

अशोकनगर जिला साडोरा तहसील के बलनाई गांव में 20 बीघा जमीन 2 लाख 27 हजार में खरीदी और यहां आकर स्थानीय लोगों की तरह परंपरागत खेती की, लेकिन उससे कोई मुनाफा नहीं हो रहा था। इसी बीच उद्यान विभाग के कुछ पदाधिकारी आए और खेत में अन्य फसलों के साथ ही आम के पेड़ लगाने की सलाह दी। 2013 में उद्यान विभाग से 175 आम के पौधे लाया और लगा दिए। इनमें से 10 पौधे नष्ट हो गए। अभी 165 आम के पेड़ बगीचे में हैं। आम के पेड़ों के बीच में खाली पड़ी जगह में फूल व सब्जी उगाता हूं, जिससे रोजमर्रा का खर्च निकल आता है। मैंने अपने खेत में 3 किस्म के आम लगाए हैं, जिसमें लंगड़ा, चौंसा और दशहरी शामिल हैं। सभी आम उन्नत किस्म के हैं। तीनों आम के हर फल का वजन करीब 200 से 400 ग्राम तक होता है। इसका सीजन साल में 3 से लेकर 4 महीने तक चलता है।

बाजार तक खुद कर रहे सप्लाई

राजेंद्र सिंह बताते हैं कि जब उनके आम का साइज फुल हो जाता है तो वह उसे खुद ही तोड़कर कार्बाइड में रखकर पकाते हैं। फिर मंडी में दुकानों पर जाकर बेच देते हैं, जिससे उनको पूरा मुनाफा मिल जाता है। दुकानों पर आम का रेट 60 रुपए प्रति किलोग्राम मिलता है। इसी तरह से खेत में लगी सब्जी और फूल को भी वह प्रतिदिन बेचने के लिए बाजार जाते हैं।

परिवार के सभी सदस्य सहयोगी

किसान राजेंद्र सिंह की 7 बेटियां हैं। पूरा कारोबार उन्होंने ही जमवाया है। कोरोना काल में पत्नी की मौत हो चुकी है। 7 में से 4 बेटियों की शादी हो चुकी है। वे बताते हैं कि परिवार के सभी सदस्य बहुत सहयोग करते हैं। जरूरत होने पर ही बाहर से मजदूर लेकर आते हैं। वैसे भी इलाके में मजदूर कम ही मिल पाते हैं। मिलते हैं तो बहुत ज्यादा पैसा मांगते हैं। जब सभी बेटियों की शादी हो जाएगी तो उन्हें मजदूरों पर ही निर्भर होना पड़ेगा। वे बताते हैं कि जिस स्थान पर आम का बगीचा है वहीं उनका पूरा परिवार रहता है।

मिला नर्सरी का लाइसेंस

राजेंद्र सिंह बताते हैं कि अब उन्हें अच्छा मुनाफा हो रहा है। प्रशासन ने उन्हें आम के बगीचे में पौधे तैयार करने के लिए नर्सरी का लाइसेंस दे दिया है। अब वे अलग-अलग वैराइटी वाले आम के पौधे तैयार करेंगे। इसका फायदा दूसरे किसानों को भी मिलेगा। वे बताते हैं कि मेरा यह उद्देश्य है कि जिले के सभी गांवों में आम की खेती हो, ताकि सभी किसानों को इसका फायदा मिले।

बागवानी से मुनाफा दोगुना

बागवानी की शुरुआत के बाद उनका मुनाफा दोगुना हो गया। पहले करीब 1 लाख 25 हजार रुपए की बचत हो पाती थी, लेकिन अब ढाई लाख रुपए बच जाते हैं। राजेंद्र सिंह बताते हैं कि उन्हें देखकर अब करीब आधा दर्जन किसानों ने आम उगाना शुरू कर दिया है।

पौधे लगाने से पहले की तैयारी

आम के पौधे तो सभी तरह की जमीन में लगाए जा सकते हैं, लेकिन अच्छी जलधारण क्षमता वाली गहरी, बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। भूमि का पीएच मान 5.5-7.5 तक इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। आम के पौधे 25-27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में लगाए जा सकते हैं। मानसून के दौरान 125 सेमी बारिश होती है, जो इसके लिए उपयुक्त है। शुरुआती तीन से चार वर्ष तक सिंचाई पर फोकस करना होता है। शुरुआत के दो-तीन वर्षों तक आम के पौधों को विशेष देखरेख की जरूरत होती है। जाड़े में पाले से बचाने के लिए व गर्मी में लू से बचाने के लिए सिंचाई का प्रबंधन करना पड़ता है।

ग्राम सेवक से मिला था आइडिया

11 साल पहले किसान का संपर्क गांव के ग्राम सेवक से हुआ। दोनों के बीच बातचीत हुई, इसी दौरान ग्राम सेवक ने उन्हें तकनीकी वाली खेती करने की सलाह दी। ग्राम सेवक ने राजेंद्र को हॉर्टिकल्चर से जुड़ी जानकारी दी। राजेंद्र सिंह उनके आइडिया से प्रभावित हुए और परंपरागत खेती छोड़कर तकनीकी खेती की तरफ रुख किया। उन्होंने आम के 175 पौधे लगाए थे, जिनमें से 165 पौधे जीवित बचे हुए हैं। इसी दौरान उन्होंने खेत में फूल और सब्जी की खेती भी शुरू कर दी।

आम के पेड़ में रोग भी कम

आम के पेड़ में सामान्यतः कम ही रोग लगता है। इसमें चौसा, दशहरी और लंगड़ा आम ऐसे हैं, जिसके फल में कोई कीट नहीं लगता। आम के फल में कभी-कभी हल्के फटने की बीमारी शुरू होती है। उसके लिए फोरेट डाल देते हैं, जिससे कीड़े पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं।

अपने आउटलेट से बेच रहे कई प्रोडक्ट

जैविक खेती में डटे हरदा के दो भाई मां बीमार हुई तो खेती की शुरुआत

हरदा। जागत गांव हमार

खाने की चीजों में मिलावट रोकने और उनकी शुद्धता को बनाए रखने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाने वाले हरदा के दो किसान भाइयों ने मिसाल पेश की है। ये हरदा जिला मुख्यालय के गोलापुरा के रहने वाले मोहनीश बादर और मोहित बादर हैं। 10 साल पहले तक इनका परिवार भी रासायनिक खेती करता था। फसलों की पैदावार भी अच्छी हो रही थी। आमदनी भी ठीक-ठाक थी। इसी दौरान इनके परिवार में कुछ ऐसा हुआ, जिसने रासायनिक खेती के प्रति इनका मोहभंग कर दिया।

10 साल पहले इनकी मां को अचानक हार्ट अटैक आया। डॉक्टर ने कहा कि रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल कर जो अनाज की पैदावार हो रही है, वो स्वास्थ्य के लिए घातक है। हेल्दी रहना है, तो कम से कम रासायनिक दवाओं का प्रयोग करें। इसी दिन दोनों भाइयों ने तय कर लिया कि अब वे रासायनिक खेती पर निर्भरता खत्म करेंगे। इसी संकल्प के तहत दोनों ने 27 एकड़ जमीन के कुछ हिस्से में जैविक खेती शुरू की। पहले सिर्फ अपने घर में उपयोग के लिए खेती की। अब घर की जरूरतों के साथ आमदनी बढ़ाने के लिए बाजार के हिसाब से भी काम करने लगे हैं। नतीजा, दोनों ने जैविक तरीके से अनाज की पैदावार कर ग्राहकों के लिए आउटलेट पर उपलब्ध करा रहे हैं। हरदा जिला मुख्यालय के गोलापुरा में रहने वाले मोहनीश बादर पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा होल्डर हैं। वहीं, उनके भाई मोहित बादर ने एमए के साथ एमएसडब्ल्यू की पढ़ाई की है।

जैविक खेती में लागत के मुकाबले मुनाफा कम होता है। हम लोगों को जैविक उत्पादों के प्रति जागरुकता की कमी की वजह से नुकसान भी उठाना पड़ा। पिताजी की डांट अलग खानी पड़ी। पिता कहते थे कि बेटों को खेतों में दिन रात मेहनत करने के बाद भी आर्थिक रूप से परेशान देखता हूं, तो दुख होता है। कुछ दिनों बाद जब उन्हें अहसास हुआ कि उनके संपर्क वाले लोग जो रासायनिक खेती करते हैं, वे बीमारियों की चपेट में हैं। इसके बाद जैविक अनाज खाने से होने वाले फायदे को समझने के बाद उन्हें बेटों पर गर्व महसूस होता है।

स्वास्थ्य के प्रति भी चिंचित

पिता अशोक बादर अब कहते हैं कि मेरे दोनों बेटे धरती माता के सच्चे पुत्र होने का फर्ज अदा कर रहे हैं। साथ ही, लोगों के स्वास्थ्य के प्रति भी चिंचित हैं। अब वे भी हम दोनों भाइयों के इस काम में कंधे से कंधा मिलाकर सपोर्ट कर रहे हैं। जब से जैविक खेती की शुरुआत की है, तब से मजदूरों की बड़ी समस्या रहती है। रासायनिक खेती में खरपतवार को खत्म करने के लिए स्प्रे किया जाता है, लेकिन जैविक खेती में खरपतवारों को हटाने मजदूरों की सहायता लेनी पड़ती है। कई बार देशी तकनीक से तैयार किए जाने वाले कीट नियंत्रण में बदबू के चलते मजदूर भी छिड़काव करने में परहेज करते हैं।

अच्छा मुनाफा भी हो रहा

मजदूरों के हाथों से खरपतवार को साफ करने में लगने वाली मजदूरी से लागत बढ़ जाती है। जैविक खेती में भले ही उत्पादन कम होता है, लेकिन जितना होता है, वह शुद्ध होता है। मैं तो कहूंगा कि हर किसान को कुल खेती के कुछ हिस्से में जैविक खेती करनी चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों को तो शुद्ध अनाज देकर बीमारियों से बचा सकते हैं। दोनों भाई बिना किसी मदद के सालों से जैविक खेती कर रहे हैं। रबी सीजन में गेहूं चना, बारिश में हल्दी व गर्मी के सीजन में मूंग की फसल लगाते हैं। इन फसलों से हमें अच्छा मुनाफा भी हो रहा है।

चने से बनी सेव से मिला प्रमोशन

आउटलेट के संचालक मोहित ने बताया कि एक बार उसकी शॉप के सामने से इंदौर का व्यक्ति गुजर रहा था। इस दौरान उसने जैविक अनाज की आउटलेट देखकर गाड़ी रोकी। शॉप पर आकर दो किलो सेव ले गया। जब उसने यह सेव उदयपुर में दोस्त को भेजी, तो उस दोस्त के जैविक चने से बनी सेव का स्वाद चखने के बाद हमें इंदौर में लगने वाले जैविक उत्पाद के मेले में स्टॉल लगाने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद यहां अच्छा रिस्पॉन्स मिला।

पांच एकड़ में कर रहे खेती

मोहित 5 एकड़ में सिर्फ जैविक खेती कर रहे हैं। बाकी जमीन में पहले की तरह की खेती हो रही है। जैविक खेती शुरू करने वालों के लिए सबसे जरूरी है कि शुरुआती दौर में लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा हम लोगों के साथ भी हुआ। तीन से चार साल तक तो ऐसा लगा जैसे गलत कदम उठा लिया हो। लंबे समय से रासायनिक खेती करने की वजह से खेत की उर्वरक क्षमता प्रभावित हो जाती है। यही वजह है कि जब आप बिना रासायनिक खाद के खेती करते हैं, तो पैदावार प्रभावित होती है। इन सब चुनौतियों के बीच अगर हार नहीं माने, तो सफलता निश्चित मिलेगी। हम लोगों के साथ भी हुआ। पहले नुकसान हो रहा था, लेकिन जैसे-जैसे खेत में जैविक खाद का असर होने लगा, उत्पादकता भी बढ़ने लगी।

जमीन पर कंपोस्ट खाद

इसे कचरे और गोबर का इस्तेमाल कर बनाते हैं। जमीन के ऊपर चार से 6 इंच मोटी गोबर की परत बनाते हैं। उसके ऊपर हरा कचरा, खरपतवार डाल देते हैं। हरा कचरा यानी गाय के खाने के बाद जो अपशिष्ट बच जाता है उसकी एक लेयर रखते हैं। सबसे ऊपर फिर से गोबर डालते हैं। इस तरह से तीन से चार लेयर बना लेते हैं। हमारे पास 80 फीट लंबा एरिया है। यहां हर छह माह में कंपोस्ट तैयार हो जाता है। इसी में केंचुआ पनपते हैं, जो कि अपशिष्ट से अपना भोजन बना लेते हैं।

दूसरा है जीवामृत

गोबर, गौमूत्र और गुड़ मिलाकर बनाते हैं। 10 किलो गोबर, 10 लीटर गौमूत्र, एक किलो गुड़, 500 ग्राम बेसन और 200 लीटर पानी मिलाते हैं। इसे लकड़ी से 12 से 24 बार एक दिन में घुमाते हैं। यह प्रक्रिया दो से तीन दिन तक चलती है। इस जीवामृत का उपयोग फसलों पर छिड़काव के लिए करते हैं। इसे छानकर अलग रखते हैं। जरूरत के मुताबिक बहते पानी में भी दे सकते हैं। एक से चार एकड़ में इसका इस्तेमाल हो जाता है।

घन जीवामृत खाद

इसमें पानी की मात्रा कम रखते हैं। गौमूत्र गोबर, गुड़, बेसन और साथ में पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी का उपयोग किया जाता है। इन पेड़ों पर आने वाले पक्षियों के अपशिष्ट यहां की मिट्टी में गिरे होते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल जैविक खाद की तरह किया जाता है। साथ ही बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे की जमीन पर लंबे समय से किसी रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं हुआ रहता है। इसलिए भी यहां की मिट्टी काफी उपजाऊ होती है। इस मिट्टी का उपयोग घन जीवामृत बनाने के लिए करते हैं।

बाजार से दोगुनी कीमत में बिकती है

रासायनिक खाद के इस्तेमाल वाली गेहूं की कीमत जहां 3000-3500 रुपए प्रति क्विंटल मिलती है। वहीं, जैविक तरीके से मिली गेहूं की पैदावार की कीमत 6000-6500 रुपए प्रति क्विंटल मिल जाती है। इसके अलावा अपने आउटलेट पर काला चना, जैविक चावल, जौ चना सत्तू, जैविक आलू, जैविक काले गेहूं आटे बिस्किट, जैविक चना बेसन के शुद्ध घी से बना मगध लड्डू, जैविक चना बेसन के सेव चना दाल मिक्स नमकीन, जैविक मूंगफली दाना लोगों की जरूरत के अनुसार छोटे-छोटे पैकेट बनाकर बेचते हैं। जैविक खाद फसलों के अवशेष, खरपतवार, पौधों की पत्तियां, गोबर, मूत्र, मुर्गी की खाद, घरेलू उपयोग किए गए पौधों के अवशेष आदि के समावेश से बनाते हैं। दोनों युवा किसान अपनी खेतों के लिए खुद ही 3 प्रकार की जैविक खाद तैयार करते हैं।

अमरनाथ यात्रा के वेस्ट मैनेजमेंट संभालने का जिम्मा

अब मध्यप्रदेश का स्टार्टअप हिमालय में कचरा फैलने से रोकेगा

भोपाल। जागत गांव हमार

सबसे दुर्गम और हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित बाबा अमरनाथ पवित्र गुफा यात्रा के वेस्ट मैनेजमेंट का जिम्मा इंदौर की स्टार्टअप कंपनी को फिर मिला है। कंपनी 350 से अधिक सफाई मित्रों और वॉलेंटियर की टीम के साथ अमरनाथ के दोनो यात्रा पथ यानि बालटाल और पहलगाम पर और गुफा तक के 13 कैंपों के माध्यम से कचरे को हिमालय में फैलने से रोकेगी। अमर नाथ यात्रा एक जुलाई से शुरू होने वाली है। यात्रा के दौरान लाखों यात्री पवित्र गुफा के दर्शन के लिए जाते है और सैकड़ों टन कचरा भी इस दौरान उत्पन्न होता है। यात्रा के वेस्ट मैनेजमेंट का जिम्मा इंदौर की

स्टार्टअप कंपनी स्वाहा को मिला है। डायरेक्टर समीर शर्मा ने बताया कि हमारी टीम सबसे पहले बेस कैंप पर ही सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकेगी और उसके लिए यात्रियों से प्लास्टिक लेकर कपड़े के थैले निःशुल्क बांटे जाएंगे। इसके बाद लंगरों के फूड वेस्ट और किचन वेस्ट से ऑन स्पॉट कंपोस्ट बनाया जाएगा। यात्री कम से कम कचरा फैलाए, इसके लिए यात्रा मार्ग पर जिंगल्स, यात्रा एंथम , विभिन्न एक्टिविटीज , सेल्फी प्वाइंट, कपड़े का बैग और साथ ही स्वच्छता मासकॉट पूरे समय बेस कैंपों में घूमेंगे।

पहाड़ों पर इंदौरी पोहा भी मिलेगा

यात्रा के दौरान इस बार स्वाहा इंदौर के सोशल मीडिया ग्रुप के साथ मिलकर एक ऐसा लंगर लगाएगा, जो पूरी तरह सोलर और बायोगैस से चलेगा और इसमें इंदौरी स्वाद यानी पोहे, साबूदना खिचड़ी, चाय यात्रियों को निशुल्क प्रसाद के तौर पर वितरित की जाएगी।

20 से 30 लाख बोतले रास्ते में फेंकते है यात्री

अमरनाथ यात्रा 62 दिन चलेगी। इस दौरान 1200 टन कचरे का एकत्र कर उसका निपटान किया जाएगा। कंपनी के रोहित अग्रवाल के अनुसार यात्रा के दौरान 20 से 30 लाख प्लास्टिक बोतलों का यात्री उपयोग करते हैं और उसे रास्ते में फेंक देते है। सबसे ज्यादा प्लास्टिक कचरा इन बोतलों के कारण ही होता है। हमारी टीम यात्रा के शुरुआती कैम्प में ही सिंगल यूज प्लास्टिक रोकेगी। कचरे को प्रोसेस करने के लिए हमने विशेष मशीनें तैयार की है जो बिजली के बगैर चलेगी। उन्हें घोड़ों की मदद से पहाड़ों पर पहुंचाया जाएगा।

समस्याओं से निपटने खोजना ही होगा जल संकट का समाधान

सत्येंद्र पाल सिंह

प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख, कृषि विज्ञान केंद्र, लहार (भिंड)

भारत सरकार द्वारा कृषि एवं पर्यावरण मंत्रालय के तहत कृषि के अंतर्गत-पर्यावरण के लिए जीवन शैली कार्यक्रम का आयोजन 20 मई से लेकर 5 जून तक किया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत जल, जंगल, जमीन, जलवायु और जनसंख्या को आधार मानकर स्वस्थ पर्यावरण के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कायक्रमों में कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। कायक्रमों के माध्यम से किसानों व ग्रामीणों के साथ आमजन में पर्यावरण से जुड़े विषयों पर जागरूकता पैदा करना है।

खेती के साथ अपने पर्यावरण को स्वस्थ रखा जाए तो बदलते जलवायु परिवर्तन से आने वाली चुनौतियों का भी सामना किया जा सकता है। देश के कई राज्यों में गर्मियां शुरू होते ही जल संकट की समस्या से जूझना पड़ता है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में सूखे की अव्यवस्था के कारण करोड़ों रुपयों की जनधन की हानि भी उठानी पड़ती है। इन राज्यों के निवासियों को सूखा के चलते जहां पलायन को विवश होना पड़ता है वहीं पालतू एवं अन्य पशुओं को असमय ही काल का ग्रास बनना पड़ता है। आज देश के कई राज्यों में भूमिगत जल के गिरते स्तर के कारण जमीन के अंदर भी सूखा के हालात पैदा हो गए हैं। देश के अधिकांश राज्यों में भूमिगत जल के अंधाधुंध व अनियोजित दोहन पर कोई प्रभावी रोक नहीं हैं। इसके चलते यह समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। यदि आने वाले वर्षों में इस और समुचित और प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति और विकराल रूप अख्तियार कर लेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि गिरते भूमिगत जल स्तर की बानगी यह है कि इसके कारण इन क्षेत्रों में हैंडपंप, निजी व सरकारी नलकूपों ने भी कार्य करना बंद कर दिया है। इस कारण बोरिंग गहरे और गहरे करने पड़ रहे हैं।

भूजल सर्वेक्षण द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार जमीन के भीतर पाए जाने वाले जल को क्रमशः तीन श्रेणियों में बांटा गया है। जिसे क्रमशः व्हाइट, ग्रे और डार्क श्रेणी में विभाजित किया गया है। जिसमें व्हाइट श्रेणी 6 से 12 मीटर, ग्रे श्रेणी 12 से 18 मीटर तथा डार्क श्रेणी को 18 से अधिक नीचे की गहराई तक चिन्हित किया गया है। गौरतलब है कि व्हाइट श्रेणी सामान्य है जबकि ग्रे श्रेणी खतरे की घंटी तथा डार्क श्रेणी खतरनाक स्तर तक पानी के नीचे सरक जाने का संकेत कराती है।

जमीन के अंदर पैदा हुए सूखे के हालात तथा भूमिगत जलस्तर का साल दर साल नीचे खिसकना सतही तौर पर मानव द्वारा स्वनिर्मित है। आज जिस तरीके से खेतों की सिंचाई से लेकर शहरों, उद्योगों, निजी उपयोग आदि में नलकूपों, पंप सेटों, समरसेबल द्वारा अंधाधुंध एवं अनावश्यक ढंग से जिस प्रकार पानी का दोहन किया जा रहा है उसके चलते यह हालात पैदा हुए हैं। वहीं गांवों में किसानों व ग्रामीणों द्वारा वर्षा जल का समुचित संग्रह न करना, तालाब, पोखरों का लोप होना है, जिससे वर्षा जल प्रतिवर्ष बेकार वह जाता है प्रमुख कारणों में से एक है।

इसके लिए जरूरत कैच दा रैन अर्थात बरसात को पकड़ो, जहाँ है जैसे है, बरसात के जल को रोकना होगा। इसलिए गांव का पानी ताल में, ताल का पानी पाताल में और खेत का पानी खेत में रोके जाने की जरूरत है जिससे वह बेकार मैं बहकर नदी-नालों में न जा सके। तालाब एवं पोखरों की नियमित साफ-सफाई और खुदाई के साथ ही खेतों की मेंड़बंदी तथा गर्मी की गहरी जुताई भी वर्षा जल संचय के लिए अति आवश्यक होती है। नजर दौड़ाई जाए तो गांवों में तालाबों की खुदाई व सफाई न

होने से इनका स्वरूप ही समाप्त होता चला जा रहा है। तालाब, पोखर, कुएं, बावड़ी, गड्ढे आदि गांवों में वर्षा जल संचय के सदियों से परंपरागत साधन रहे हैं। जिसमें हर वर्ष संचित होने वाले वर्षा जल का उपयोग वर्षा उपरांत फसलों की सिंचाई पशुओं व मानव आदि के लिए होता रहा है। यही संचित वर्षा जल के कारण भूमिगत जल स्तर भी स्थाई रूप से ऊपर बना रहता है। लेकिन सिंचाई सुविधाओं की बढ़ोतरी होने तथा नलकूपों, पंपिंग सेटों आदि की अधिकता के चलते बोरिंग कर पानी निकालने के दौर में परंपरागत ढंग से जल संचय की प्रवृत्ति की और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। फलस्वरूप तालाब-पोखर आदि का अस्तित्व समाप्त हो चला गया। वर्षा जल की कृत्रिम रिचार्ज तकनीकी को भी अमल में नहीं लाया जा रहा है। इस कारण वर्षा जल संचयन या रीचार्ज नहीं होने के कारण वह व्यर्थ बहकर चला जाता है। साथ ही भूमिगत जल के दोहन का दौर भी बदस्तूर जारी है।

कुछ दशकों पूर्व तक गावों में अधिकांश मकान कच्चे मिट्टी के होते थे जिसकी प्रतिवर्ष गर्मीओं मैं तालाब की चिकनी मिट्टी से लिपाई व मरम्मत आदि का कार्य किया जाता था। इसके लिए तालाबों का गावों मैं महत्वपूर्ण स्थान होता था। बरसात से पूर्व गर्मियों में तालाब एवं पोखर का पानी कम होकर दलदल में तब्दील होता जाता था। उसी समय ग्रामीण इसी चिकनी दलदल युक्त मिट्टी को तालाब से निकालकर अपने घरों की लिपाई व लिसाई में प्रयोग करते थे। जिसके चलते लगभग समस्त ग्राम वासियों द्वारा मिट्टी निकालने से तालाबों की स्वत: ही सफाई हो जाती थी। इसके बाद बरसात में इनमें वर्षा जल संचयन होकर उपयोग में पूरे साल उपयोग मैं आता रहता था। साथ ही तालाब में पूरे वर्ष जलभराव के चलते भूजल स्तर भी नीचे नहीं गिरता था। आज गावों मैं अधिकांश मकान पक्के बन जाने के कारण इस प्रकार की प्रक्रिया पर पूर्ण विराम लग चुका है। हालांकि केंद्र व राज्य सरकारें इस दिशा में कई परियोजनाएं लेकर आई हैं। खेत तालाब से लेकर अमृत सरोवर तक पर कार्य किया जा रहा है।

जल संकट के समाधान के लिए आवश्यकता इस बात की है कि वर्षा जल को बेकार बह जाने से रोकना होगा। इसके लिए तालाबों, पोखर, बावड़ी आदि को पुनर्जीवित करना ही होगा। गिरते भूमिगत जल के स्तर को ऊपर उठानें के लिए कृत्रिम रिचार्ज तकनीकी भी अपनानी होगी। ऐसा करने से वर्षा जल को परंपरागत ढंग से एकत्र करने के साथ ही वैज्ञानिक ढंग से भी रिचार्ज करना होगा। वैज्ञानिक तरीके से पानी को जमीन के अंदर संरक्षित करने के लिए रिचार्ज तकनीकी को भी अमल में लाना आवश्यक हो जाता है। वाटर सेट प्रबंधन के अंतर्गत बारिश के पानी को संरक्षित करने के लिए जगह-जगह एवं गांव-गांव कच्चे पक्के तालाब बनाने होंगे। इसके अलावा भूगर्भ जल के पुनर्भरण हेतु रिसन तालाब भी बनाकर जलस्तर को गिरने से रोका जा सकता है। वाटर हार्वेस्टिंग जैसी तकनीकी को भी गांव स्तर पर अमल में लाने की जरूरत है। इस प्रकार से यदि 15 से 20 फ़ीसदी भी वर्षा जल का सही ढंग से भूगर्भीय संग्रह कर लिया जाए तो भावी जल संकट को काफी हद तक टाला जा सकता है। जल संकट के समाधान हेतु सरकार व ग्राम पंचायतों को मिल जुलकर सच्चे मन से प्रयास करने होंगे। इसी वर्ष से वर्षा जल के संचयन को लेकर ग्राम पंचायतों द्वारा ग्रामीणों को साथ लेकर पहल करनी चाहिए। आवश्यकता इस बात की भी है कि प्रत्येक ग्रामीण व शहरी लोगों को जल संरक्षण के समुचित प्रबंधन के साथ ही भूमिगत जल का अनावश्यक एवं अंधाधुंध प्रयोग करने से अपने आप को रोकना ही होगा। तभी कहीं जाकर जल संकट का उचित समाधान किया जाना संभव है।

गाय एवं भैंसों में पटार का संक्रमण एवं समाधान

» डॉ. शुभ्रदल नाथ
» डॉ. गिरिधारी दास
» डॉ. सुमन कुमार
» डॉ. रुपेश वर्मा
» डॉ. संजू मंडल
» डॉ. हरि आर तिवारी
» डॉ. अजय राय
» डॉ. विक्रम पूनिया

पशु परजीवी विज्ञान विभाग, पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, जबलपुर, ना.दे.प.चि.वि.वि., जबलपुर

पटार या पटेरे गोल कृमि होते हैं, जो कि गाय एवं भैंसों के बछड़ों एवं बछियों की छोटी आंत में पाया जाता है। इसका प्रकोप भैंसों के पाड़ों एवं पड़िया में ज्यादा देखा जाता है। यह एक गोल कृमि है, एवं अंग्रेजी में इसे टोक्सोकारा विटुलोरम के नाम से जाना जाता है। यह बछड़ों एवं बछियों की आंतों में पाया जाने वाला एक एस्केरिड परजीवी है। इस कृमि का संक्रमण आर्थिक महत्व का है, मुख्य रूप से जो पशु रूग्ण और किसी बीमारी से संक्रमित होते है उनमें यह मृत्यु का कारण भी बन सकता है। हालांकि यह परजीवी दुनिया भर में हो सकता है, परंतु इनका प्रकोप उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले देशों में ज्यादा देखा जाता है।

पटार गोल कृमि सामान्यत: पशुओं की छोटी आंतों में पायी जाती है। एवं शरीर को मिलने वाले पोषण का अपने स्वविकास के लिए उपयोग करती है। जब इनकी संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो यह आंतों का मार्ग अवरूद्ध कर देती है। इनका प्रकोप एक माह या इससे कम आयु के बछड़ों में ज्यादा होता है। एवं पटेरे बछड़ों एवं बछियों में करीब करीब 50 प्रतिशत मृत्यु का कारण बनते है। जिससे पशु पालकों को जन-धन की हानी होती है।

इसका संचरण और जीवन चक्र वयस्क जानवरों एवं बछड़ों में भिन्न होता है।

1. वयस्क गाय एवं बछड़ों में कृमि के अण्डों के द्वारा जिनके अंदर लार्वा होता है वह पानी एवं चारे से पशुओं में अंत: गृहित किया जाता है। यह लार्वा एल-2 स्टेज का होता है एवं यह शरीर के विभिन्न अंगों और अवशेषों में जाकर निष्क्रिय पड़ा रहता है, इसे हाइपोबायोटिक लार्वा के रूप में जाना जाता है।

2. बछड़ों एवं पाड़ों में इस कृमि का संचरण दो तरह से होता है, मादा से उसके अजन्मे बच्चें में जिसे प्रीनेटल संचरण कहते हैं। इस अवस्था में लार्वा गर्भाशय को पार कर बच्चे के यकृत में चला जाता है। दूसरा प्रसव पश्चात निष्क्रिय लार्वा जो कि वयस्क मादाओं में होते हैं वह सक्रिय होकर थन ऊतकों में चले जाते हैं एवं दूध में स्रावित होने लगते हैं। इसे ट्रांसकोलसट्रल/ ट्रांसमेमेरी संचरण कहते हैं। इसके बाद यह लार्वा छोटी आंत में जाकर करीब 38 - 40 दिन बाद वयस्क हो बछड़ों के मल से निकलने लगता है।

पटारों के द्वारा व्याधीजनन एवं लक्षण: सामान्य अवस्था में पटारों के संक्रमण का दुष्प्रभाव कम होता है। और बहुत समय तक पहचाना भी नहीं जाता इनका व्याधीजनन संक्रमित पशुओं इनकी संख्या पर निर्भर करता है, यदि इनकी संख्या 100 से 500 हो जाती है तब बीमारी का पता पशुपालकों को लगता है अत्यधिक संक्रमण की अवस्था में जानवर की मृत्यु भी जाती है। प्रभावित जानवारों को मिट्टी अथवा कीचड़ के रंग का दस्त होने लगता है। उनके मल से एक विशेष प्रकार की दुर्गंध आने लगती है। जानवर सुश्त एवं कमजोर दिखने लगता है। उनके बाल खुरदुरे एव चमक विहीन हो जायेंगे। कभी-कभी पेट फूल जाता है। संक्रमण ज्यादा होने पर बछड़ा दर्द के कारण लोट-पोट करने लगता है। पशुओं के मल से सफेद केंचुए जैसा जीव बाहर आता है।

बीमारी का निदान: बीमारी के निदान के लिए पशुओं के मल की जाँच करवाते हैं, इनके मल की जाँच शासकीय पशुचिकित्सालय में निम्न शुल्क देकर करवाया जा सकता है। मल की जाँच सूक्ष्म दर्शी द्वारा किया जाता है। संक्रमण होने पर कृमि का अण्डा दिखता है जो कि गोलाकार होता है एवं उसके चारों तरफ छलनी के आकार का घेरा होता है।

बीमारी का उपचार एवं नियंत्रण के उपाय: किसान भाईयों (पशुपालकों) से अनुरोध है कि किसी भी बीमारी का उपचार स्वयं न करें। किसी रजिस्टर्ड पशुचिकित्सक की सलाह से या उनके द्वारा दी गई सलाह का पालन करें। इनका उपचार पायरेंटल पामोइट 25 मि.ग्रा. प्रति कि.ग्रा. भार की दर 7 दिनों तक देने से सामान्यत: जानवर ठीक हो जाता है। इसके अलावा बछड़ों को पिपराजिन 110 मि.ली. प्रति कि.ग्रा. भार की दर से दिया जा सकता है। एलबेंडाजोल 5-10 मि.ली प्रति कि.ग्रा. भार की दर से दिया जा सकता है। गाभिन पशुओं में फेनबेंडाजोल 5-10 मि.ली प्रति कि.ग्रा. भार की दर से दिया जा सकता है। मिनरल मिक्सचर एवं लवण की भरपाई पशुचिकित्सक की सलाह से करनी चाहिए।

बीमारी की रोकथाम एवं नियंत्रण लिए फार्म या बाड़ों में साफ-सफाई रखनी चाहिए। चूँकि बछड़ों में यह रोग सबसे अधिक होता है इसलिए गर्भवती मादा पशु व दूध देने वाले पशुओं को पहले से ही कृमिनाशक दवाई पिला देनी चाहिए। यह रोग वयस्क पशुओं में दूषित चारा, दाना के खाने से होता है, इसलिए चारा व दाना एवं पानी स्वच्छ और साफ होना चाहिए। बाड़े का मलमूत्र साफ रखना चाहिए। बछड़ा एवं बछियों को दसवें दिन, बीसवें दिन एवं तीसवें दिन कृमिनाशक दवाई पिलानी चाहिए।

कार्य योजना उपयुक्त हो तो कम वर्षा भी बन सकती है वरदान

भारतीय मौसम विभाग ने अध्ययन के अनुसार इस वर्ष खरीफ 2023 में मध्य भारत के अधिकांष क्षेत्रों में 20 से 40 प्रतिषत तक वर्षा में कमी की आषंका व्यक्त की गई।

» डॉ. आरडी बारपेटे
» डॉ. मेघा दुबे
वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केन्द्र, बैतूल

जून एवं जुलाई के माह में सामान्य से कम (20 से 40 प्रतिशत) वर्षा का अनुमान है। मप्र के अधिकांश जिलों में सोयाबीन, मक्का एवं धान खरीफ के मौसम में 90 प्रति. तक क्षेत्राच्छादन करती हैं। मौसम विभाग की भविष्यवाणी को ध्यान में रख खरीफ कार्य योजना में निम्न प्रौद्योगिकी को अपनाएं तो कम वर्षा भी हमारे शुद्ध लाभ को कम नहीं कर पाएगी।

फसलों का चयन: खरीफ की कार्य योजना बनाते समय कम पानी में पकने वाली फसलों को प्राथमिकता देवें। कम से कम 20-25 प्रतिशत क्षेत्र में ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, सांवा, मूंग, उड़द, आदि में से कोई दो या तीन फसलों को स्थान देवें। ये फसलें न सिर्फ कम पानी में उत्पादित होती हैं, बल्कि फसल चक्र के लाभ भी प्रदान करती हैं। इन सभी फसलों की उत्पादन लागत भी सोयाबीन, मक्का, धान आदि से कम हैं। अतएव ये शुद्ध लाभ को बढ़ाएंगी।

प्रजातियों का चयन: प्रमुख फसलें जैसे सोयाबीन की शीघ्र पकने वाली प्रजाति जे.एस. 20-34, जे.एस. 95-60 आदि, मक्का की हायेसेल, जे.एम.-216, आदि, धान की दंतेष्वरी, बी.व्ही.डी. 109 आदि को स्थान दें। ये प्रजातियां अल्प वर्षा की स्थिति में भी लाभदायक रहती हैं।

बोने की विधि: सोयाबीन एवं मक्का को अनिवार्य रूप से मेड़नाली पद्धति से बुवाई करें। मेड़नाली पद्धति से बोनी करने पर अतिवृष्टि में जल निकास एवं अल्पवृष्टि में नमी संरक्षण होता है। धान की भी रोपाई विधि के स्थान पर सीधी बोनी करें। इस तकनीकी में भी कम पानी की आवष्यकता होती है। मक्का, धान, ज्वार आदि की मानसून पूर्व शुष्क बोनी करें। मानसून के आगमन पर पैनी नजर रखें एवं आगमन की संभावना होने पर शुष्क बोनी करें। कुटकी, सांवा आदि फसलों को भी छिटकवा विधि से न बोयें एवं कतार में बोनी करें। लम्बी बतर की स्थिति में इन फसलों में भी कोल्पे चलाकर नमी का संरक्षण किया जा सकता है।

खरपतवार प्रबंधन: खरीफ फसलों में खरपतवारों से सर्वाधिक हानि होती है। वर्तमान समय में अंकुरण के पश्चात् प्रयुक्त होने वाले खरपतवारनाषियों का बहुतायत से प्रयोग हो रहा है। इन रसायनों को नमी की अवस्था में ही उपयोग कर सकते हैं और अल्पवर्षा की स्थिति में इन रसायनों का प्रयोग कठिन हो जायेगा। अत: बोनी के पश्चात् एवं अंकुरण के पूर्व प्रयोग होने वाले पेंडीमिथेलिन (1 लीटर प्रति हेक्टेयर) का प्रयोग करें। जिन फसलों की शुष्क बोनी की हैं, उन फसलों में वर्षा होने पर अगले 3 दिन के अंदर इस दवाई का या ज्वार, मक्का में अट्राजिन 2.5 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें। रासायनिक खरपतवार प्रबंधन के अलावा कोल्पे चलाने की तैयारी भी रखें। यह कार्य खरपतवार प्रबंधन के साथ-साथ नमी संरक्षण भी करेगा।

उर्वरक प्रबंधन: खरीफ फसलों में पोषक तत्वों की संपूर्ण मात्रा रासायनिक उर्वरक से न दें। संपूर्ण पोषक तत्व रासायनिक उर्वरक से देने के पश्चात् यदि नमी की कमी हुई तो फसलों को अधिक हानि होती है और लागत भी अधिक होती है। अत: आधी मात्रा रासायनिक उर्वरकों से एवं आधी मात्रा जैविक उर्वरकों से या केंचुआ खाद, गोबर की खाद के माध्यम से देवें। ये जैव/कार्बनिक खाद भूमि की जैविक, रासायनिक एवं भौतिक दषा को ठीक करते हैं तथा नमी संरक्षण के साथ हवा का संचार सुधारते हैं जिससे विपरीत परिस्थिति में भी उत्पादन हानि कम होती है।

30 मई तक जमा होगे नामांक फार्म, वोटिंग 13 जून को

एक पंचायत में सरपंच, 114पंचायतों में 555 पंच पदों के लिए होगा चुनाव

श्योपुर। जागत गांव हमार

ग्राम पंचायत डोब में सरपंच पद के लिए 13 जून को फिर से वोटिंग होगी। इसके साथ ही जिले की ग्राम पंचायतों में रिक्त बने 555 पंच पदों के लिए चुनाव होगा। पंचायत उप चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना जारी होने से जहां प्रशासन ने चुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं चुनाव लड़ने के लिए ईच्छुक लोगों ने भी अपने-अपने क्षेत्र के मतदाताओं से संपर्क साधना आरंभ कर दिया है। जनपद पंचायत कराहल की ग्राम पंचायत डोब के निर्वाचित सरपंच की एक सड़क के दौरान मृत्यु हो गई। इसलिए ग्राम पंचायत डोब का सरपंच पद रिक्त बना हुआ है। वहीं जिले की 114 ग्राम पंचायतों में 555 पंचों के पद खाली रह गए है। रिक्त बने इन पदों पर फिर से चुनाव कराया जाएगा। बताया गया है कि जो लोग इस चुनाव में लड़ने का मन बना रहे है, वे नामांकन भी दाखिल कर सकते है। गत 23 मई से नामांकन दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो गया है। संबंधित तहसील कार्यालयों में नामांकन पत्र दाखिल करने का सिलसिला 30 मई तक चलेगा। जबकि 31 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 2 जून को नाम वापसी के तुरंत बाद चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए जाएंगे। इसके बाद 13 जून को आवश्यकता लगने पर वोटिंग कराई जाएगी। वोटिंग के लिए सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे का समय निर्धारित किया गया है। वोटिंग के तुरंत बाद ही मतगणना भी शुरू हो जाएगी और शाम तक जीत हार का फैसला चल जाएगा। लेकिन सरपंच पद के विधिवत परिणाम की घोषणा 17 जून और पंच पद के परिणाम की घोषणा 19 जून को की जाएगी।

श्योपुर में सबसे ज्यादा पंचों के पद खाली

जिले में सबसे ज्यादा पंचों के पद जनपद पंचायत श्योपुर की ग्राम पंचायतों में रिक्त बने हुए हैं। इसके बाद दूसरा स्थान जनपद पंचायत कराहल और तीसरा स्थान जनपद विजयपुर की ग्राम पंचायतों का आता है। बताया गया है कि जनपद पंचायत श्योपुर की 50 ग्राम पंचायतों में 237 पंचों के पद रिक्त है। वहीं जनपद पंचायत कराहल की 26 ग्राम पंचायतों में 189 तथा जनपद पंचायत विजयपुर की 38 ग्राम पंचायतों में 129 पंचों के पद रिक्त है। जिन पर फिर से चुनाव होगा।

फैक्ट फाइल

01 सरपंच पद पर होगा चुनाव

237 पंच पद श्योपुर में खाली

189 पंच पद कराहल में रिक्त

129 पंच पद विजयपुर में रिक्त

मृतक के परिवार को फिर से मौका देने की चर्चा

ग्राम पंचायत डोब में सरपंच पद को लेकर होने वाले उप चुनाव में मृतक सरपंच रामबीर आदिवासी के परिवार के किसी सदस्य को फिर से मौका देने की चर्चा ग्रामीणों के बीच चल रही है। बता दें कि मृतक रामबीर आदिवासी के परिवार की ग्राम पंचायत क्षेत्र में अच्छी पकड़ है। इसलिए चुनाव में रामबीर आदिवासी की जीत हुई थी, लेकिन एक परिचित की मदद करने के लिए जाने के दौरान उसकी सड़क हादसे में मौत हो गई। इसलिए लोग इस परिवार के किसी सदस्य को फिर से सरपंच बनाने की चर्चा कर रहे हैं।

कृषि विज्ञान केंद्र में कृषक गोष्ठी का आयोजन

किसानों को खेती बाड़ी के साथ दिलाई गई स्वस्थ पर्यावरण अपनाने की शपथ

लहार (भिंड)।

कृषि के अंतर्गत पर्यावरण के लिए जीवन शैली कार्यक्रम के क्रम में कृषि विज्ञान केंद्र पर वर्षा जल संचयन और उसके कुशल उपयोग के लिए जागरूकता पैदा करना एवं बारिश को पकड़ो विषय पर किसान जागरूकता कार्यक्रम एवं कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया. इस दौरान किसानों को खेती बाड़ी के साथ स्वस्थ पर्यावरण अपनाने की शपथ भी दिलाई गई।

इस अवसर पर किसानों को संबोधित करते हुए केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ एस पी सिंह ने बताया कि पृथ्वी पर जितना भी पानी है उसका 97 प्रतिशत पानी समुद्र में खारे जल के रूप में विद्यमान है। सिर्फ 3 प्रतिशत पानी ही मीठे जल के रूप में पाया जाता है जिसमें से 2.5 प्रतिशत पानी पहाड़ों पर ग्लेशियर के रूप में जमा है जो पिघलकर नदियों के माध्यम से लोगों को उपलब्ध होता है और यह भी अधिकांश पानी नदियों के माध्यम से होते हुए समुद्र में खारे पानी में मिल जाता है। जमीन के अंदर पाए जाने वाला भूगर्भ जल मात्र 0.5 प्रतिशत ही है। इस भूगर्भ जल पर ही पीने के पानी से लेकर खेतीवाड़ी और उद्योग के लिए पानी की निर्भरता है। लगातार भूगर्भ जल के दोहन के कारण जमीन के भूमिगत जलस्तर में भारी गिरावट देखी जा रही है। साल दर साल यह भूगर्भ जल नीचे खिसकता जा रहा है। इतना ही नहीं नीचे जा रहा हूं भूमिगत जल भी खारी हो रहा है। उन्होंने बताया कि यदि किसान भाई हर साल होने वाली वर्षा के जल को संचित करने की ओर ध्यान नहीं देंगे को जमीन का जलस्तर नीचे गिरने के साथ-साथ पानी भी खारी होता जायेगा। इसलिए किसानों को चाहिए गांव का पानी ताल में, ताल का पानी पाताल में और खेत का पानी खेत में रोकने का हर संभव प्रयास करें। खेतों में वर्षा जल को अधिक से अधिक संचित करने के लिए खेतों की मेढ़बंदी के साथ-साथ गर्मी की गहरी जुताई को अमल में लाएं।

3द्धद्बद्य53द्ध द्बद्यद्मद्ध53द्ब द्म53द्धस्रद्यद्ब 000द्धस्र53

अवगत कराना है कि कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा दिनांक 20 मई से 5 जून तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के निर्देशानुसार पर्यावरण के लिए जीवन शैली कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत- जलवायु अनुकूल फसलें व प्रजातियां, स्मार्ट कृषि, विश्व पर्यावरण दिवस, जैविक एवं प्राकृतिक कृषि एवं मृदा स्वास्थ्य पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज केंद्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रमुख रूप से केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ करणवीर सिंह, डॉ अवधेश सिंह, डॉ नरेंद्र सिंह भदौरिया डॉ रूपेंद्र कुमार, निशांत प्रभाकर एवं दीपेंद्र शर्मा आदि प्रमुख रूप से शामिल थे। इस अवसर पर केंद्र के प्रमुख डॉ एस पी सिंह द्वारा किसानों को स्वस्थ पर्यावरण की शपथ भी दिलाई।

इंदौर में मालवा किसान मेला-2023 का किया शुभारंभ

उन्नत खेती और अधिक उत्पादन के लिए कृषि मेले का लाभ लें: पटेल

भोपाल। जागत गांव हमार

किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि किसान मेले का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। उन्नत खेती और अधिक उत्पादन के लिए तकनीकी ज्ञान से स्वयं को समृद्ध करें। उन्होंने कृषि कॉलेज इंदौर में मालवा किसान मेला-2023 का शुभारंभ किया। मंत्री ने मेले में किसानों को कृषि रत्न सम्मान से सम्मानित किया और किसान मेले का अवलोकन भी किया। मेले में दर्शन सिंह चौधरी, महिपाल सिंह, अन्य जन-प्रतिनिधि और कृषक उपस्थित थे।

कृषि मंत्री ने कहा कि किसान मेले में उन्नत खेती करने के तरीके बताये जाएंगे। यहां बताया जाएगा कि आधुनिक खेती कैसे करें, गुणवत्तायुक्त उत्पादन कैसे हो, किसानों को अपनी उपज का अधिक से अधिक मूल्य कैसे प्राप्त हो, इन सभी का मेले में बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा। किसान भाइयों से आह्वान है कि वे मेले का अधिक से अधिक लाभ लें, जिससे उत्पादन वृद्धि में मदद मिल सके।

मंत्री ने कहा कि किसान परिवार के बच्चे अब उच्च शिक्षित हो रहे हैं। हम सभी उन्हें खेती के साथ कृषिगत व्यापार और उद्योग के लिए भी प्रोत्साहित करें। सरकार किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सतत प्रयासरत है। सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। किसानों के अच्छे दिन आये हैं। इसीलिये बेहतर योजनाएं बना कर लाभान्वित किया जा रहा है। अब सरकार और किसानों के मध्य कोई बिचौलिया नहीं है।

मंत्री ने कहा कि हमारा देश गांव और किसानों का देश है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए तत्कालीन समय में ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के लिए 68 प्रतिशत राशि का प्रावधान बजट में किया था। उन्होंने कहा था कि गांव को विकास के लिए समुचित राशि उपलब्ध कराना जरूरी है। उनके समय में शुरू हुई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना गांव के विकास के लिए क्रांतिकारी साबित हुई है।

कृषि वैज्ञानिकों की सलाहः नरवाई का उपयोग कम्पोस्ट, कार्बनिक खाद और केंचुआ खाद बनाने में करें

भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने किसान न जलाएं पराली

नरसिंहपुर। जागत गांव हमार

जिले के किसानों को कृषि विज्ञान केन्द्र नरसिंहपुर के वैज्ञानिकों ने जानकारी दी है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए और भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए पराली(नरवाई/पुआल) नहीं जलाए। कृषि विज्ञान केन्द्र नरसिंहपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. विशाल मेश्राम ने कहा कि नरवाई जलाने से भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने में सहायक कृषि सहयोगी सूक्ष्म जीवाणु तथा जीव भी नष्ट हो जाते हैं किसान ही अन्नदाता है। पर्यावरण के संरक्षक हैं इसलिए नरवाई को जलाने की बजाए उसका अन्य उपयोग करें, जिससे उन्नत खेती, पशु-चारे की उपलब्धता और सभी को स्वच्छ प्राण वायु मिल सकें। इस संबंध में केन्द्र के वैज्ञानिक डॉ. आशुतोष शर्मा ने बताया कि नरवाई का उपयोग कम्पोस्ट/कार्बनिक खाद/केंचुआ खाद बनाने में, मशरूम/पिहरी/खुम्बी उत्पादन में, बायोचार बनाने में, बिजली उत्पादन में फसल अवशेष का उपयोग बीकेट्स बनाने में, फसल अवशेष का बायोफ्यूल एवं बायो ऑयल उत्पादन में प्रयोग, छोटे पशुपालक फसल अवशेष का उपयोग रस्सी/टाट पट्टी, फेंसिंग तैयार करने में, फसल अवशेष का उपयोग बिछावन(मल्चिंग) के लिए करे, फसल अवशेष का उपयोग पैकेजिंग, चावल की भूसी ब्रायलर उत्पादन में, फसल अवशेषों के साथ खेती करें।

किसानों के लिए फायदेमंद

केन्द्र की वैज्ञानिक डा. निधि वर्मा ने बताया कि नरवाई को जलाने की बाजाए उसे भूमि और पशुचारे में तब्दील करना ज्यादा उपयोगी है। विशेषज्ञों का सुझाव उर्जा उत्पादन तथा कार्ड-बोर्ड और कागज बनाने में किया जा सकता है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार नरवाई जलाए बिना उसी के साथ गेहं की बोवनी की जा सकती है। साथ ही जब नरवाई सड़ेगी तो खाद मे बदल जाएगी और उसका पोषक तत्व मिट्टी में मिलकर गेहूं की फसल को अतिरिक्त लाभ देगा। उन्होंने कहा कि अब तो ऐसे यंत्र भी उपलब्ध है जो आसानी से ट्रेक्टर में लगाकर खड़े डंठलों को काटकर इकट्ठा कर सकते है और उन्हीं में बोवनी भी की जा सकती है। दोनों ही विकल्प किसानों के लिए फायदेमंद है।

नरवाई जलाने से चैतरफा नुकसान

केन्द्र के वैज्ञानिक डॉ. एसआर शर्मा ने बताया कि नरवाई जलाने से वातावरण को चैतरफा नुकसान होता है और जमीन के पोषक तत्वों के नुकसान से साथ प्रदूषण भी फैलता है। ग्रीन हाउस गैसे पैदा होती है, जो वातावरण को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती है। केन्द्र के वैज्ञानिक डॉ. विजयसिंह सूर्यवंशी ने जानकारी दी कि खेत में फसल अवशेषों को जलाने से नत्रजन 80 प्रतिशत, फास्फोरस 25 प्रतिशत, पोटाश 20 प्रतिशत और सल्फर 50 प्रतिशत जैसे मुख्य पोषक तत्व एवं सूक्ष्म पोषक तत्व और कृषि सहयोगी सूक्ष्म जीवाणु जल कर नष्ट हो जाते हैं फसल अवशेषों को जलाने से 70 प्रतिशत कार्बन डाई आक्साइड, 7 प्रतिशत कार्बन मोनो आक्साइड, 0.66 प्रतिशत मिथेन और 2.1 प्रतिशत नाईट्रोजन आक्साइड गैसे निकलती है जो कि पर्यावरण को प्रदूषित करती है जिससे गंभीर बिमारिया फैलती है।

खासियतः सिर्फ दो महीने में फसल हो जाएगी तैयार, उत्पादन भी होगा ज्यादा

मटर की नई किस्म 'काशी पूर्वी' किसनों को बनाएगी आत्मनिर्भर

वाराणसी। जागत गांव हमार

मटर की खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ने मटर की एक ऐसी किस्म को विकसित किया है, जिसकी बोवनी करने पर बंपर पैदावार मिलेगी।

इस किस्म की खासियत है कि यह कम समय में तैयार हो जाएगी। ऐसे में किसानों को सिंचाई और खाद का उपयोग भी कम करना पड़ेगा, जिससे हजारों रुपए की बचत होगी। यह एक तरह की मटर की अगेती किस्म है, जिसकी खेती से किसानों की आय बढ़ जाएगी। वाराणसी स्थित आईआईवीआर ने मटर की इस नई किस्म का नाम 'काशी पूर्वी' रखा है। 'काशी पूर्वी' की खासियत है कि यह 65 दिन में ही तैयार हो जाएगी। यानी कि किसान 65 दिन बाद फसल की कटाई कर सकते हैं। हालांकि, अभी मटर की जिस किस्म की खेती की जा रही है, उसकी फसल को तैयार होने में 80 से 85 दिन लग जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मटर की नई किस्म 20 दिन पहले ही तैयार हो जाएगी। वहीं, 'काशी पूर्वी' की पैदावार भी पारंपरिक मटर के मुकाबले ज्यादा है। एक हेक्टेयर में खेती करने पर 115 से 120 क्विंटल तक मटर का प्रोडक्शन होगा। ऐसे में किसान भाई अगर 'काशी पूर्वी' की खेती करते हैं, जो ज्यादा कमाई कर सकेंगे।

अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से लेकर नवंबर के पहले हफ्ते के बीच बुवाई

भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के डॉ. ज्योति देवी और डॉक्टर आर के दुबे ने 'पूर्वी काशी' किस्म को विकसित किया है। किसान भाई 'काशी पूर्वी' को अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से लेकर नवंबर के पहले हफ्ते के बीच बुवाई कर सकते हैं। एक हेक्टेयर में 120 किलो बीज की बुवाई करनी होगी। इससे अच्छी पैदावार मिलेगी। डॉ। ज्योति देवी का कहना है कि इस मटर की आधुनिक विधि से खेती करने की जरूरत है। इसके बीज की बुवाई 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर करनी चाहिए। साथ ही पंक्तियों के बीच 30 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। बुवाई के 35 दिन बाद ही फसल में फूल आने लगते हैं। 65 दिन बाद आप मटर की तुड़ाई कर सकते हैं।

एक हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक उपज

काशी पूर्वी की खासियत है कि इसके एक पौधे में 10 से 13 फलियां लगती हैं। एक हेक्टेयर में खेती करने पर 120 क्विंटल तक उपज मिलेगी। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ. टीके बेहरा का कहना है कि काशी पूर्वी को खरीफ और रबी सीजन के दौरान भी बोया जा सकता है। इस फसल के ऊपर सफेद चूर्ण आशिता और रतुआ रोग का प्रभाव न के बराब पड़ने वाला है।

टीकमगढ़ में प्राकृतिक खेती और श्री अन्न फसलों को लगेगा पंख

कृषि निदेशक, कृषि तकनीकी अनुप्रयोग अनुसंधान ने कृषि विज्ञान केंद्र में ली बैठक और दिए सुझाव

टीकमगढ़। जागत गांव हमार

कृषि विज्ञान केन्द्र, टीकमगढ़ में दिनांक 23 मई 2023 को डॉ. एसआरके सिंह, निदेशक, कृषि तकनीकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान जोन-9, जबलपुर द्वारा केन्द्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. बीएस किरार एवं अन्य कृषि वैज्ञानिकों के साथ प्रदर्शन इकाईयों, प्राकृतिक खेती एवं श्री अन्न फसलों को जिले में बढ़ावा देने एवं आगामी माह जून के मध्य में वृहत कृषि विज्ञान मेला का आयोजन को दृष्टिगत रखते हुए बैठक ली गई। कृषि विज्ञान मेला मुख्य रूप से केन्द्रीय किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, भारत सरकार मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर के मुख्य अतिथ्य में आयोजित होना है । विस्तृत चर्चा के साथ ही कृषि विज्ञान मेला के लिए स्थल का भी निरिक्षण किया गया।

वैज्ञानिकों को दिया निर्देश

बैठक मे खरीफ-2023 की कार्ययोजना अनुसार कार्यक्रम का क्रियान्वयन सुचारू रूप से सरलता एवं सफलता पूर्वक किस प्रकार से किया जाये, इसके विषय पर विस्तृत चर्चा के साथ-साथ निदेशक द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी वैज्ञानिक पूर्व निर्धारित खरीफ 2023 के कार्ययोजना को ध्यान में रखते हुये जिले में कार्य करें। निदेशक द्वारा केन्द्र के विभिन्न प्रदर्शन ईकाईयों मुर्गी पालन, बकरी पालन, औषधीय गार्डन, हरी खादय, प्राकृतिक खेती ईकाई का भ्रमण किया गया। बैठक में मुख्य रूप से वैज्ञानिक डॉ. आरके प्रजापति, डॉ. एसके सिंह, डॉ. यूएस धाकड़, डॉ. आईडी सिंह, हंसनाथ खान एवं मनोहर चढ़ार उपस्थित रहे।

वैज्ञानिकों का कमाल, विकसित किया ऐसा पेड़, जिसमें होंगे 12 किस्म के आम

रांची। जागत गांव हमार

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक ही पेड़ पर 12 किस्म के आम की खेती की प्रणाली विकसित की है। आईसीएआर के पूर्वी प्रक्षेत्र रांची स्थित अनुसंधान केंद्र ने यह तकनीक विकसित की है। इन पेड़ों पर एक साथ दशहरी, मालदह, मल्लिका, जर्दालू, तोतापरी, हिमसागर, प्रभाशंकर जैसी प्रजातियों के फल उग रहे हैं। अब इस तकनीक से इलाके के किसानों को अवगत कराया जा रहा है। इसी केंद्र ने एक ही पौधे में बैगन और टमाटर की खेती में भी तकनीक भी

विकसित की है। 100 से ज्यादा किसानों ने प्रायोगिक तौर पर इस खेती की शुरुआत भी कर दी है। यह केंद्र रांची के प्लांडू में स्थित है। प्लांडू एक वैज्ञानिक ने बताया कि आम के एक ही पेड़ पर एक दर्जन प्रजातियों के फल उगाने की यह तकनीक ग्राफ्टिंग के जरिए काफी पहले विकसित कर ली गई है, लेकिन अब पहली बार किसानों को इस तकनीक का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके बाद किसानों को इसके लिए पौधे भी उपलब्ध कराए जाएंगे और खेती के दौरान उन्हें तकनीकी मदद भी दी जाएगी।

एक ही पौधों पर बैगन -टमाटर की खेती

एक अन्य वैज्ञानिक पी भावना ने बताया कि इस केंद्र ने एक ही पौधे पर बैगन और टमाटर की खेती की जो प्रणाली विकसित की है, उसे ब्रिमैटो नाम दिया गया है। ब्रिंजल (बैगन) और टोमेटो (टमाटर) को एक पौधे में उगाने की यह प्रणाली किचन और रूफटॉप गार्डन के लिए उपयुक्त है। इसके एक पौधे की कीमत 80 रुपए है। जिन 100 किसानों को पहले चरण में पौधे उपलब्ध कराए गए हैं, उन्हें सफलता मिली तो इसकी खेती व्यापक पैमाने पर शुरू की जाएगी।

-दोनों संभागों में मसालों, औषधीय पौधों की खेती, आम और अन्य फलों को दें बढ़ावा

कृषि उत्पादन आयुक्त ने कहा-फसल विविधीकरण को दें बढ़ावा और करें प्रोत्साहित

रीवा-शहडोल के किसान करते हैं धान-गेहूं की बोवनी, समय पर मिले खाद और बीज

भोपाल। जागत गांव हमार

कमिश्नर कार्यालय तथा कलेक्ट्रेट के एनआईसी केंद्र में आयोजित वीडियो कान्फ्रेंसिंग में कृषि उत्पादन आयुक्त वीरा राणा ने रीवा तथा शहडोल संभाग के कृषि आदान की समीक्षा की। उन्होंने आगामी फसल के लिए खाद, बीज एवं कीटनाशकों की उपलब्धता के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। कृषि उत्पादन आयुक्त ने कहा कि किसानों को फसल विविधीकरण के लिए प्रोत्साहित करें। रीवा और शहडोल संभाग में किसान मुख्य रूप से धान और गेहूं की फसल पर केंद्रित हैं। किसानों को बाजार की मांग के अनुसार अनाजों की खेती के लिए प्रोत्साहित करें। सिंगरौली, अनूपपुर और रीवा जिले में कृषि विविधीकरण के लिए अच्छे प्रयास हुए हैं। अनूपपुर और सिंगरौली में कोदो तथा कुटकी की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। रीवा संभाग में फल तथा सब्जियों का अच्छा उत्पादन हो रहा है। यहां सब्जियों तथा फलों की खेती क्लस्टर में की जा रही है। दोनों संभागों में मसालों, औषधीय पौधों की खेती, आम और अन्य फल-सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा दें। कृषि के क्षेत्र में विकास होने से रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। कई शिक्षित युवा भी सफलतापूर्वक खेती, पशुपालन एवं मछलीपालन कर रहे हैं।

कृषि उत्पादन आयुक्त ने सहकारी बैंकों की समीक्षा करते हुए कहा कि रीवा संभाग के सभी जिलों में सहकारी बैंकों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। कलेक्टर बैंकों के कार्यों की नियमित समीक्षा करें। लंबित ऋणों की वसूली के लिए आरआरसी जारी कराएं। रीवा और सतना में गत वर्षों की तुलना में वसूली बढ़ी है।

सभी 2 लाख रुपए तक के डिफाल्टर किसानों को मुख्यमंत्री व्याज माफी योजना में पंजीयन कराकर उन्हें योजना का लाभ दें। इससे किसानों तथा बैंक दोनों को फायदा होगा। दोनों संभागों में पर्याप्त मात्रा में खाद तथा बीज उपलब्ध हैं। खाद की नियमित रैक लग रही हैं। गत वर्ष 30 जून तक समितियों तथा अन्य क्षेत्रों में खाद की जितनी बिक्री हुई थी उससे अधिक खाद अब तक जिलों में भंडारित की जा चुकी है। किसी भी स्थिति में खाद की आपूर्ति में कमी नहीं आएगी।

रीवा संभाग में पशुओं की संख्या अधिक

कृषि उत्पादन आयुक्त ने कहा कि पशुपालन विभाग की विभागीय योजनाओं में सभी जिलों में अच्छा कार्य हुआ है। रीवा संभाग में पशुओं की संख्या बहुत अधिक है। दुधारू पशुओं की नस्ल सुधार का विशेष अभियान चलाएं। रीवा जिले में 20 हजार लीटर प्रतिदिन दूध ठंडा करने वाला संयंत्र स्थापित किया जा चुका है। संभाग में नए मिल्क रूट तथा दूध सहकारी समितियां बनाकर दूध के संग्रहण को बढ़ावा दें। रीवा में बसामन मामा गौ-अभ्यारण्य में निराश्रित तथा आवारा गौवंशों को बड़ी संख्या में रखने एवं वहां गोबर-संयंत्र जैविक खेती आदि से जोड़कर बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। कमिश्नर रीवा तथा शहडोल अपने संभाग के सभी कलेक्टरों एवं अन्य अधिकारियों को इसका भ्रमण कराएं। रीवा जिले में अभी लम्पी रोग का खतरा बना हुआ है इसके लिए पूरी सावधानी बरतें।

फूलों और स्ट्राबेरी की खेती हो रही

बैठक में रीवा संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारी ने कहा कि संभाग के सभी जिलों में फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। रीवा जिले में फल एवं सब्जी उत्पादन तथा पशुपालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। सहकारी बैंक के कार्यों की नियमित समीक्षा की जाएगी। बैठक में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने रीवा जिले में खाद्य प्रसंस्करण, मछलीपालन, पशुपालन तथा डेयरी के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिले के कई उच्च शिक्षित युवा आधुनिक तरीके से कृषि, पशुपालन तथा मधुमक्खीपालन जैसे व्यवसाय कर रहे हैं। फूलों और स्ट्राबेरी की खेती भी की जा रही है। बैठक में मंडी बोर्ड, दुग्ध संघ, कृषि अभियांत्रिकी के कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के भी निर्देश दिए गए।

खेती को लाभ का धंधा बनाएं

बैठक में प्रमुख सचिव कृषि अशोक वर्णवाल ने कहा कि सभी कलेक्टर जिले की कृषि विकास की कार्ययोजना बनाने में ध्यान दें यह केवल अकड़ों की बाजीगरी नहीं है जिले की कृषि विकास की कार्ययोजना में भूमि, सिचाई की उपलब्धता तथा खेती से जुड़े वास्तविक तथ्यों को शामिल करें। खेती के विकास तथा कृषि विविधीकरण के लिए सही तथ्यों को शामिल करते हुए कार्ययोजना बनाए। इसमें खेती की आधुनिक तकनीक, परंपरागत खेती के अच्छे गुणों, किसानों की कठिनाइयों को दूर करने के उपायों तथा खेती को लाभ का धंधा बनाने के उपायों को शामिल करें। उप संचालक कृषि केवल खाद, बीज बांटने के लिए फसल प्रदर्शन न लगाये। फसल प्रदर्शन के माध्यम से किसानों को आधुनिक तकनीक से परिचित कराएं। एक जिला एक उत्पात योजना में चिन्हित गतिविधियों के विस्तार तथा इसे बाजार से जोड़ने के प्रयास करें।

शोध: जल्द कुछ नहीं किया तो नतीजे खतरनाक होंगे

गर्मी का असर, गाय-भैंसों नेकम किया दूध देना क्या करें पशुपालक

भोपाल। जागत गांव हमार

ग्रामीण इलाकों में किसान तेजी से गाय और भैंस पालन की ओर प्रोत्साहित हो रहे हैं। इससे किसान दूध बेचकर बढ़िया मुनाफा तो कमा ही रहे हैं। इसके अलावा किसानों उन्हें अपनी खेतों के लिए गाय के गोबर के तौर पर मुफ्त खाद भी मिल रही है, लेकिन तापमान में वृद्धि दुधारू पशुओं पर काफी बुरा असर पड़ रहा है। देशभर के अधिकतर राज्यों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। महाराष्ट्र में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। बढ़ते तापमान के चलते किसानों के साथ-साथ जानवर भी परेशान हैं। बढ़ते तापमान का सीधा असर दुधारू पशुओं के दूध उत्पादन पर हो रहा है। तपती धूप के चलते दुधारू पशु चारा कम खाते हैं, जिसके चलते दूध उत्पादन में 15 प्रतिशत तक की गिरावट आ सकती है। दूध उत्पादन कम होने के चलते किसानों को आर्थिक रूप से भी नुकसान हो रहा है।

दुधारू पशुओं पर भीषण गर्मी का बुरा असर: भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुपालन का एक अहम रोल है। ग्रामीण इलाकों में किसान तेजी से गाय और भैंस पालन की ओर प्रोत्साहित हो रहे हैं। इससे किसान दूध बेचकर बढ़िया मुनाफा तो कमा ही रहे हैं। इसके अलावा किसानों उन्हें अपनी खेतों के लिए गाय के गोबर के तौर पर मुफ्त खाद भी मिल रही है, लेकिन तापमान में वृद्धि दुधारू पशुओं पर काफी बुरा असर पड़ रहा है।

तापमान में आई वृद्धि किसानों पर मुसीबत का सबब बन रहीं है। धूप कि तपिश और लू लगने के कारण दुधारू पशुओं ने दूध देना कम कर दिया है। जानवरों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए उनके शेड में फॉगर लगाया है। साथ ही उनके लिए एक बड़ा सा स्विमिंग टैंक भी बनाया है।

पशुओं को गर्मी से बचाने के लिए अपनाएं ये उपाय

पशु चिकित्सकों के अनुसार अचानक वृद्धि से जानवरों पर बूरा असर पड़ रहा है। भीषण गर्मी पड़ने के चलते जानवर तनाव की स्थिति में हैं। इसके चलते वह चारा कम खाते हैं। इसका असर दूध पर भी होता है। इस साल बढ़ती धूप के कारण जिले के दूध उत्पादन में 15 प्रतिशत की गिरावट आई है। भीषण गर्मी से पशुओं को ज्यादा नुकसान न हो इसके लिए उन्हें ठंडा पानी पिलाते रहें, उन्हें छांव में रखें। उनको ठंडे पानी से नहलाए। ये सब नहीं करने की स्थिति में पशु बीमार भी हो सकते हैं।

सोलर रूफटॉप पर सरकार दे रही अनुदान

भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने आमजन एवं उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने घर, ग्रुप हाउसिंग सोसायटी की छत, लगी हुई खुली जगह पर सोलर पैनल लगायें और बिजली पर होने वाले खर्च को बचायें। कंपनी ने बताया है कि एक बार सोलर ऊर्जा पैनल लगाने से लगभग 25 साल तक निरंतर बिजली मिलती रहेगी। सोलर से उत्पादित बिजली के मूल्य को देखते हुए सोलर पैनल लगाने पर हुए व्यय का भुगतान अगले 3-4 वर्ष में बराबर हो जाएगा। लाभ अगले 20 वर्ष तक मिलता रहेगा।

कितनी मिलेगी सब्सिडी: एक किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा पैनल के लिए लगभग 100 स्क्वायर फुट जगह की जरूरत होती है। भारत सरकार द्वारा आमजन/उपभोक्ताओं को 3 कि.वा. तक के सोलर प्लांट पर 40 प्रतिशत सब्सिडी और 3 किलोवाट के बाद 10 किलोवाट तक 20 प्रतिशत सब्सिडी एवं ग्रुप हाउसिंग सोसायटी को कॉमन सुविधा वाले संयोजन पर 500 किलोवाट तक (10 किलोवाट प्रति घर) 20 प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है। कंपनी द्वारा अधिकृत एजेंसी, तकनीकी विवरण, सब्सिडी और भुगतान की जाने वाली राशि की जानकारी के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

अनुदान के लिए आवेदन कहाँ करें

उपभोक्ता द्वारा संदेश एप से सरलीकृत प्रक्रिया से केन्द्र सरकार के नेशनल पोर्टल www.solarrooftop.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन के बाद कंपनी के अधिकृत वेंडर्स से सोलर पैनल लगाने का कार्य कराया जा सकता है। सोलर रूफटाप योजना में मिलने वाली सब्सिडी की राशि केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ता के खाते में स्वत: जमा करवा दी जायेगी।

सोलर पैनल की क्षमता	सब्सिडी(रु. में)
1 किलोवाट	14588
2 किलोवाट	29176
3 किलोवाट	43764
4 किलोवाट	51058
5 किलोवाट	58352
6 किलोवाट	65646
7 किलोवाट	72940
8 किलोवाट	80234
9 किलोवाट	87528
10 किलोवाट	94822
10 से 100 किलोवाट	94822
100 से 500 किलोवाट	94822

कब कितनी प्रजाति के पक्षी मिले

वर्ष	प्रजाति
2019	226
2020	222
2021	220
2022	246

विलुप्ति की कगार पर पहुंचीं गिद्धों की पांच प्रजातियां मिली

मंदसौर के गांधीसागर अभयारण्य में मौजूद हैं 246 तरह के पक्षी

गौरव तिवारी, जागत गांव हमार,मंदसौर।

मंदसौर गांधीसागर अभयारण्य में जहां चीतों के आने की तैयारी की जा रही है, वहीं एक और खुश खबरी है कि यहां अभी तक 246 प्रजाति के पक्षी मिले हैं। इसमें सबसे खास बात यह है कि जिस तरह से अभयारण्य में पक्षियों की विलुप्त प्राय और असुरक्षित प्रजातियां मिली है। उससे ऐसा लग रहा है कि अभयारण्य क्षेत्र संकटापन्न पक्षी की प्रजातियों के आवास एवं रहवास के लिए अनुकूल है। इनमें गिद्धों की विलुप्त हो रही पांच प्रजाति भी शामिल है। इसके अलावा कुछ असुरक्षित प्रजातियां भी यहां मिली है। विशेषज्ञों का कहना हैं पक्षियों की जो प्रजातियां संकट में हैं उनका यहां मिलना संकेत दे रहा है कि अभयारण्य में उनके जीवन के लक्षण है। गांधीसागर अभयारण्य में पिछले साल हुए पक्षी सर्वेक्षण का डाटा संकलन पूरा हुआ है। पूरे डाटा का पक्षी विशेषज्ञों द्वारा विश्लेषण कर एक सूची तैयार की है। इसमें ग्रेट थिकनी (स्टोन कर्ली) पक्षी कुछ साल पहले पहली बार दिखाई दिया है। वह अभी भी दिख रहा हैं। वहीं कई विदेशी व देशी सहित अभी तक 246 से अधिक प्रजातियों के पक्षी अभयारण्य क्षेत्र में होने की जानकारी मिली है।

देशभर से 80 प्रतिभागी एवं विशेषज्ञ शामिल हुए

पक्षी सर्वेक्षण में कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात एवं अन्य राज्यों के लगभग 80 प्रतिभागी एवं पक्षी विशेषज्ञ शामिल हुए थे। जो तीन दिन तक 23 रास्तों, गणना लाइनों पर निकले थे। गणना के पश्चात प्राप्त पूरे डाटा का डब्ल्यूएनसी वाइल्ड लाइफ एण्ड नेचर कंजरवेंसी इंदौर, एनजीओ के पक्षी विशेषज्ञों द्वारा विश्लेषण कर सूची तैयार की गई।

गिद्धों की विलुप्त प्रजातियां मिली | इन प्रजातियों में आइयूसीएन की रिड डाटा बुक अनुसार गंभीर रूप से विलुप्तप्राय: प्रजातियां जैसे लांग बिल्ड वल्चर, रेड हेडेड वल्चर, व्हाइट रम्पेड वल्चर, स्टेपी इगल, इजिप्टियर वल्चर मिली है। यह सभी गिद्धों की प्रजातियां हैं। इसके अलावा असुरक्षित प्रजातियां जैसे सारस क्रेन, कामेन पोचार्ड, वोली नेक स्टोक आदि भी गांधीसागर अभयारण्य में पाई गई है।

पक्षियों की यह प्रजातियां भी प्रमुख रूप से मिली | रेड क्रस्टेड पोचार्ड, रेड नेवड फाल्कन, क्रेस्टेड हाक ईगल, ह्वाइट बेलिड मिनिवेस्ट, डेसर्ट व्हीटीयर, छोटे कान वाला उल्लू, ब्राउन फिश उल्लू, पेंटेड सैंड्याउस, मोटल्ड उल्लू, स्पाटेड रेड शंक, फेरुजिनस पोचार्ड, डालमतीन पेलीकैन, टफ्टेड डक।

जिस तरह से अभयारण्य से पक्षियों की विलुप्तप्राय: और असुरक्षित प्रजातियां मिली है। उससे ऐसा लग रहा है कि अभयारण्य क्षेत्र संकटापन्न पक्षी प्रजातियों के आवास एवं रहवास के लिए अनुकूल है। अभी तक 246 प्रजातियां यहां चिन्हित हो चुकी हैं।
आदेश श्रीवास्त, वन मंडलाधिकारी

बढ़ रहा विलुप्तप्राय ढोर और लाल तिलकधारियों का कुनबा

चंबल नदी कछुओं का स्वर्ग

मुरैना। जागत गांव हमार

घड़ियालों के लिए पहचानी जाने वाली चंबल नदी कछुओं के लिए भी स्वर्ग है। यहां कई ऐसी प्रजाति के कछुए पाए जाते हैं, जो अन्य नदियों से सालों पहले विलुप्त हो चुके हैं। अच्छी बात यह है कि इन विलुप्त प्राय कछुओं का वंश चंबल में तेजी से बढ़ रहा है। इसी कारण नदी का पानी स्वच्छ है, जिसमें अन्य जलीय जीवों का कुनबा भी बढ़ रहा है। चंबल नदी में कुल नौ प्रजाति के कछुए पाए जाते हैं, इसमें सबसे विशेष वाटागुर डोंगोका कछुआ या श्री स्टिप्ड रूफ टरटल (ढोर कछुआ) है, जिसके कवच पर तीन धारियां होती हैं। दूसरी विलुप्तप्राय प्रजाति वाटागुर कछुआ की है, जिसे गर्दन व सिर के ऊपर लाल व सफेद रंग की धारियों के कारण लाल तिलकधारी के नाम से जाना जाता है। इन दोनों को नदी का स्वच्छताकर्मी माना जाता है, क्योंकि ये प्रजाति नदी के पानी को दूषित करने वाले घास-फूस से लेकर मृत कीट, पतंगे व प्रदूषण बढ़ाने वाली मछली व अन्य जलीयजीवों को अपना आहार बनाती हैं। इसीलिए घड़ियाल अभयारण्य प्रशासन इन दोनों प्रजाति के कछुओं के संरक्षण पर जोर दे रहा है। इसके अलावा हरडेला धुरजी, टेंट टेरियन और सरकम डाटा कछुआ भी है, जिनके कवच से गोली भी पार नहीं जाती। कछुओं की चार प्रजाति निलसोनिया गेंजेटिका, लिसमस पंटाटा, निलसोलिया ह्यूरम और चित्रिका इंडिका नाजुक कवच वाले होते हैं।

भिंड-मुरैना और श्योपुर में मौजूदगी

भिंड की सांकरी हेंचुरी में वाटागुर डोंगोका व लाल तिलकधारी कछुओं के 3500 अंडे सहेजकर रखे गए हैं, जिनसे इस मई-जून में बच्चे निकलेंगे। पिछले साल 7500 अंडों का संरक्षण किया गया था, जिनमें से निकले बच्चों को चंबल में छोड़ा गया। कछुओं के 200 बच्चों की परवरिश के लिए भिंड के बरही में कछुआ सेंटर बनाया गया है। दो साल की उम्र होने पर नदी में छोड़ा जाएगा। नदी किनारे जहां-जहां रेत है वहां-वहां मादा कछुए अंडे देती हैं। श्योपुर के पाली से लेकर कतन्नीपुरा, रघुनाथपुर, नदीगांव, बटेश्वरा मुरैना में भर्रा, डांगबसई, राजघाट, गड़ौरा, टिकरी, रिठौरा, उसैद घाट से लेकर भिंड में बाबूसिंह का घेर, दलजीत का पुरा, अटेर, बरई और उप्र से सटे सांकरी तक नदी किनारे रेत में भरपूर अंडे पाए जाते हैं। मादा कछुआ फरवरी-मार्च में रेत के नीचे गड्ढे बनाकर उनमें अंडे देती हैं, जिनसे मई के अंत या जून में अंडे निकलते हैं।

चंबल नदी में कभी कछुओं की गणना नहीं हुई, लेकिन नदी में हर जगह कछुओं की मौजूदगी, प्रजनन के लिए मिलने वालों अंडों की संख्या से स्पष्ट है कि चंबल में बहुत अच्छी संख्या में कछुए हैं। वाटागुर डोंगोका व वाटागुर कछुए अधिकांश नदियों से लगभग विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन ये चंबल में अच्छी संख्या में पाए जाते हैं।
स्वरूप दीक्षित, डीएफओ, चंबल घड़ियाल अभयारण्य

-समर्थन पर गेहूं 2015 रुपए क्विंटल में खरीदा था

रतलाम में 56 फीसदी किसानों ने गेहूं बेचा, अभी 230 करोड़ खाते में पहुंचे

रतलाम। जागत गांव हमार

रतलाम जिले में इस वर्ष गेहूं का बंपर उत्पादन हुआ है। किसान मंडियों में गेहूं बेचने के साथ ही समर्थन मूल्य पर भी गेहूं बेचने में पीछे नहीं है। पिछले वर्ष के मुकाबले समर्थन मूल्य पर इस वर्ष गेहूं बेचने के लिए किसानों ने बहुत ज्यादा उत्साह दिखाया है। गत वर्ष जहां 32 हजार 624 किसानों ने पंजीयन कराया था, लेकिन मात्र 5007 किसानों ने ही समर्थन मूल्य पर 32 हजार 624 टन गेहूं शासन को बेचा था। इस वर्ष पंजीकृत 27 हजार 86 किसानों में से अब तक 15 हजार 268 (56.36 फीसद) किसान एक लाख 27 हजार 74 टन गेहूं समर्थन मूल्य पर शासन को बेच चुके हैं।

पिछले वर्ष शासन ने समर्थन मूल्य पर गेहूं 2015 रुपए क्विंटल में खरीदा था, जबकि इस बार 2125 रुपए क्विंटल में खरीदा जा रहा है। किसानों व व्यापारियों का कहना है कि गत वर्ष 95 प्रतिशत गेहूं अच्छी क्वालिटी का हुआ था, इस कारण ज्यादातर किसानों ने खुले बाजार में गेहूं बेचा था। इस वर्ष ओलावृष्टि व बारिश के चलते 20 से 25 प्रतिशत फसल को नुकसान पहुंचा और उनकी चमक फीकी पड़ गई।

समर्थन पर नहीं खरीदा जा रहा

इस बार भी बाजार में अच्छे गेहूं के दाम 2200 से 2600 क्विंटल तक है, लेकिन ओलावृष्टि व बारिश से प्रभावित गेहूं के भाव खुले बाजार में 2125 रुपए से ज्यादा नहीं आ रहे है, वे ही किसान समर्थन मूल्य पर गेहूं बेच रहे है। कई किसानों का गेहूं तो समर्थन मूल्य पर भी नहीं खरीदा जा रहा है। ऐसे में किसानों का गेहूं 1850 से 2100 रुपए क्विंटल तक खुले बाजार में बिक रहा है।

13 हजार 706 किसानों को मिला भुगतान

जिले में बनाए गए 66 खरीदी केंद्रों पर अब तक 15 हजार 268 किसान गेहूं बेच चुके हैं। इनमें से शासन 13 हजार 706 किसानों को उनके बैंक खातों में 230 करोड़ का भुगतान कर चुका है। गेहूं बेचने के सात दिन बाद भुगतान किया जा रहा है।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- **अरविंद मिश्र, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)